साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 02-08 सितंबर 2024 वर्ष-10, अंक-20

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

ग्वालियर आरआईसीः मुरैना, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर में केंद्र प्रारंभ

गांव की ओर चले उद्योगपति

भोपाल। प्रधान संपादक

सीएम डॉ. मोहन यादव की मेहनत रंग लाई। सीएम के प्रयासों से ही ग्वालियर अंचल अंचल में औद्योगिक घराने बड़ा निवेश करने के लिए राजी हो गए हैं। अडाणी ग्रुप गुना में दो मिलियन टन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट और शिवपुरी में डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ ही बदरवास में पूरी तरह से महिला ऑपरेटेड जैकेट फैक्ट्री लगाई जाएगी। ये इन्वेस्टमेंट 3500 करोड़ का होगा। वहीं, अंबानी ग्रुप ने भी 150 करोड़ का निवेश करने पर सहमति जताई है। अंचल में अंबानी समूह ने फर्टिलाइजर और बायोगैस क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल नीतियों और वातावरण के साथ प्रशासनिक स्तर पर भी स्वागत व अभिनंदन का भाव रहेगा। प्रदेश में सकारात्मक सोच के साथ औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। ग्वालियर आरआईसी में 8 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे 35 हजार से अधिक रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने 1586 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 47 नई औद्योगिक इकाइयों का सिंगल क्लिक से भूमिपूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रीजनल कॉन्क्लेव मात्र कहने के लिए रीजनल हैं, हकीकत में यह कॉन्क्लेव राज्य स्तरीय है। इन औद्योगिक इकाइयों के प्रारंभ होने से स्पंदन पूरे प्रदेश में होना है। मंच पर पांच औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन पत्र भी प्रदान किए गए। इसके साथ ही ग्वालियर-चंबल जिले के 8 जिला स्तरीय इंडस्ट्री फेसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। ये केन्द्र ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर में आज से ही प्रारंभ हो गए हैं। कॉन्क्लेव में मेक्सिको, जाम्बिया के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। ग्वालियर में निजी क्षेत्र में बड़ा चिकित्सालय भी खोला जाएगा। कॉन्क्लेव के आयोजन के पीछे यह भाव भी है कि उद्योगपति प्रदेश की विशेषताओं को आकर स्वयं देखें और मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापना का निर्णय लें।

जेसी मिल के श्रमिकों की समस्या होगी दूर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अनुकूलता से उद्यमशीलता का विकास और तीव्र गति से संभव है। उद्योग और निवेश की दृष्टि से ग्वालियर प्रमुख केंद्र रहा है। राज्य सरकार ने इंदौर की हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को मुआवजा राशि दिलवाने का कार्य किया गया है। यह कार्य अनेक वर्ष से लंबित था। औद्योगिक इकाइयों की समस्याएं भी हल होना चाहिए। अब ऐसे अन्य मामलों के लिए जरूरी निर्णय लिए जाएंगे। जेसी मिल ग्वालियर की समस्या भी हुकुमचंद मिल की तर्ज पर हल की जाएगी।

चार नए औद्योगिक पार्क

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर चिकित्सा और हेल्थ सेक्टर में ग्वालियर में एक निजी क्षेत्र का बड़ा अस्पताल प्रारंभ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर-चम्बल क्षेत्र में 4 नए औद्योगिक पार्क खोले जाने की घोषणा की। इसमें गुना के चेनपुरा में 333 हेक्टेयर, ग्वालियर जिले के मोहना में 210 हेक्टेयर, मुरैना के मवई में 210 हेक्टेयर और शिवपुरी के गुरावल में 30.64 हेक्टेयर में औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे।

चंबल की बदल जाएगी तस्वीरः सिंधिया

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में उद्योग की अलख जगाने का कार्य किया है। इस अंचल के प्रत्येक नागरिक के दिल में उन्होंने स्थान बना लिया है। ग्वालियर अंचल में अधोसंरचना और निवेश की शुरुआत वर्षों पहले की गई। वर्तमान में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की क्षमताओं के अनुकूल प्रदेश को राष्ट्रीय पटल पर लाने का कार्य किया है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की पहल करने वाले वे पहले मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश में 6 माह की अवधि में एक लाख 84 हजार करोड़ का निवेश आना सामान्य बात नहीं है। निश्चित ही ग्वालियर-चंबल क्षेत्र की तस्वीर नए-नए उद्योगों के आने से बदल जाएगी।

विकास में समग्रता को अपनायाः तोमर

विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विगत 10 वर्ष में भारत की साख में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। विकास में समग्रता को अपनाया गया है। भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, अब तीसरी अर्थव्यवस्था बने इस संकल्प से कार्य हो रहा है। ग्वालियर की पावन धरा पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन अहम है। मुख्यमंत्री प्रदेश में संतुलित और समग्र विकास के लिए प्राण-पण से जुटे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी क्षेत्रों में कार्य जरूरी होता है।

अनुदान दे रहा मप्रः काश्यप

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि सम्पूर्ण प्रदेश में औद्योगीकरण के लक्ष्य से कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है। प्रत्येक जिले में युवाओं को उद्यमी बनाया जा रहा है। वर्तमान में पारदर्शी प्रक्रिया लागू की गई है। मध्यप्रदेश उद्योगों को सर्वाधिक अनुदान देने वाला प्रदेश है।

सिर्फ महिलाएं बनाएंगी जैकेट

अडाणी समूह के करण अडाणी ने कहा कि ग्वालियर में यह कॉन्क्लेव आर्थिक प्रगति को बढ़ाएगी। अडाणी ग्रुप प्रदेश में गुना और शिवपुरी में दो नई औद्योगिक इकाइयां प्रारंभ करेगा। शिवपुरी में 2500 करोड़ की लागत से रक्षा क्षेत्र में, गुना में 500 करोड़ की लागत से सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट और बदरवास में जैकेट निर्माण इकाई शुरू की जाएगी।

500 महिलाओं को रोजगार मिलेगा

रिलायंस समूह के उपाध्यक्ष विवेक तनेजा ने कहा कि मप्र में समूह द्वारा बायो गैस और एनर्जी जनरेशन क्षेत्र में निवेश का विचार है। ट्रोपोलाइट के एमडी पुनीत डॉवर ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश प्रस्ताव की जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री की पहल से बेंगलुरू से लेकर ग्वालियर तक हुई इन्वेस्टर्स समिट और इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को रोजगार वृद्धि में सहायक बताया।

उद्योगपति का नाम-पद	इकाई का नाम	सेक्टर	निवेश	रोजगार
अंकुर गुप्ता, डायरेक्टर	प्लेग्रो इण्डस्ट्रीज	टॉय मेन्युफेक्चरिंग	30 करोड़	500
आशीष मोहापात्रा, सीईओ	ओएफबी टेक	फायनांस एण्ड आईटी	350 करोड़	15000
अचिन अग्रवाल, एमडी	प्राइम गोल्ड	स्टील	250 करोड़	100
चन्दर भूषण मिश्र, एमडी	एसएसजी फर्निशिंग	टेक्निकल टेक्सटाइल	750 करोड़	9000
अरुण गोयल, चेयरमेन	एलिक्सर इण्डस्ट्रीज	फर्नीचर एण्ड केमिकल	1000 करोड़	750
पंकज चावला, एमडी	मार्बल विनाइल	पैकेजिंग एण्ड रियर्स	620 करोड़	2800
आरपी माहेश्वरी, सीएमडी	मॉडर्न टेक्नोप्रोजेक्ट्स	हॉस्पिलिटी	100 करोड़	150
एसपीएस कोहली, ईडी	जमना ऑटो	ऑटो कम्पोनेंट	532 करोड़	200
जेएल तापड़िया	द सुप्रीम इण्डस्ट्रीज	प्लास्टिक	265 करोड़	75
राहुल संघवी	संघवी फूड्स	फूड प्रोसेसिंग	12.57 करोड़	50

- सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा-सकारात्मक सोच से उद्योगों के विकास का समन्वित प्रयास
- मध्यप्रदेश सरकार ग्वालियर में खुलेगी बड़ा निजी चिकित्सालय
- ग्वालियर आरआईसी में प्राप्त हुए 8 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव
- भिंड, शाजापुर, धार, नीमच जिलो में 1586 करोड़ की 47 इकाइयों का शुभारंभ
- ग्वालियर-चम्बल संभाग में 8 इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन सेंटर प्रारंभ
- जेसी मिल के मजदूरों के बकाया राशि का भुगतान करेगी सरकार
- सीतापुर में पुलिस चौकी और बानमोर में फायर स्टेशन खुलेगा

औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन

रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 120 औद्योगिक इकाइयों को 268 एकड़ भूमि आवंटित कर आशय-पत्र जारी किए गए। इसमें 1680 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश होगा। 6600 लोगों को रोजगार मिलेगा। एमएसएमई विभाग अंतर्गत 19 इकाइयों के लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किए गए, जिसमें 265 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश एवं लगभग एक हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रतीक स्वरूप 5 इकाइयों को भूमि आवंटन के आशय-पत्र प्रदान किए।

कॉन्क्लेव के मुख्य आकर्षण

- 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने सहभागिता की, जिसमें कनाडा, नीदरलैंड, टोगो, जाम्बिया और मैक्सिको के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए।
- 15 राज्यों के निवेशकों ने सहभागिता की। पर्यटन, आईटी, फुटवेयर, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उद्योगपति थे, जिन्होंने निवेश के लिए रुचि दिखाई।
- 400 से अधिक बायर-सेलर मीट हुईं। 5 से अधिक औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। उद्योगपतियों ने अपने अनुभव साझा किए।
- 20 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों और उद्योग संगठनों के साथ वन-टू-वन चर्चा हुई। 6 सेक्टोरल सत्र और तीन राउंड टेबल बैठकें हुई।
- अडाणी समूह द्वारा 3500 करोड़ की लागत से गुना में 2 मिलियन टन सीमेंट प्रोजेक्ट एवं शिवपुरी में प्रोपेलेंट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया।
- रिलायंस समूह ने रिन्युएबल एनर्जी गैस एवं बायो गैस प्रोजेक्ट के लिए निवेश प्रस्ताव दिया। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 2000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- ट्रोपोलाईट फूड ग्रुप द्वारा फूड प्रोसेसिंग के लिये 100 करोड़ के निवेश से अपना व्यवसाय मध्यप्रदेश में और बढ़ाने का प्रस्ताव दिया।
- मुरैना के सीतापुर में पुलिस चौकी और बामोर में फायर स्टेशन की घोषणा। ग्वालियर एवं चंबल संभाग के सभी 8 जिलों में इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ किया।
- ग्वालियर - आरआईसी में अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुए।

प्राकृतिक खेती और देशी बीजों का महत्व तेजी से बढ़ रहा

स्वदेशी बीजों से किसान ने खोजी 100 बेहतरीन फसलों की उन्नत प्रजातियां

रघुवंशी 30 वर्षों से जैविक खेती और बीजों की उन्नत किस्मों के विकास में लगे

भोपाल। जागत गांव हमार

आज कल प्राकृतिक खेती और देशी बीजों का महत्व तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यह कोई नई सोच नहीं है। देश के कई किसान बहुत पहले से ही इन पद्धतियों को अपनाने लगे थे। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों और संकर बीजों के दुष्प्रभावों को समझते हुए अपने 30 साल पहले स्वदेशी बीद और जैविक खेती की ओर रुख किया। ऐसे ही एक सजग किसान हैं श्रीप्रकाश सिंह रघुवंशी, जो अपनी खेती, अपना बीज, अपना खाद, अपना स्वाद के नारे को बुलंद करने वाले एक प्रगतिशील किसान के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के तड़िया गांव के निवासी, 64 वर्षीय रघुवंशी ने केवल 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। लेकिन उनका कृषि के प्रति समर्पण और खेती में स्वेदेशी बीजों और जैविक खेती में नवाचार से 30 सालों में 100 किस्मों की खोज करके उन्हें देशभर में प्रसिद्ध किया है।

रघुवंशी पिछले 30 वर्षों से जैविक खेती और स्वदेशी बीजों की उन्नत किस्मों के विकास में लगे हुए हैं। उन्होंने गेहूं, धान, सरसों और अरहर जैसी प्रमुख फसलों की कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जिनसे जैविक खेती के माध्यम से रासायनिक खेती की तुलना में बेहतर पैदावार प्राप्त की जाती है। उनका कहना है कि उन्होंने प्राकृतिक रूप से बीज विकसित करने का हुनर अपने पिताजी से सीखा, जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे, लेकिन उन्नत किस्म की खेती करते थे। अपने पिताजी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से ही उन्होंने कृषि में नवाचार की दिशा में कदम बढ़ाया। बाद में उन्हें नई किस्में विकसित करने की प्रेरणा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के पूर्व प्रोफेसर डॉ. महातिम सिंह से मिली, जिन्होंने उन्हें ऐसी किस्में विकसित करने के लिए प्रेरित किया जो किसानों की आय में सुधार कर सकें।

बीज संरक्षण के लिए मिला पीएम का सहयोग

प्रकाश रघुवंशी कहते हैं कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बड़ी संख्या में इन किस्मों का संरक्षण करना चुनौतीपूर्ण हो रहा था। हालांकि ये प्रजातियां पोषण और उत्पादन की दृष्टि बेहद अच्छी हैं, इसलिए गेहूं की प्रजातियों को जर्मप्लाज्म संरक्षित करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से पत्र लिख कर अनुरोध किया कि वे अपनी अस्सी गेहूं की प्रजातियों को भारत सरकार को दान करना चाहते हैं। रघुवंशी के इस पत्र को संज्ञान में लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने गेहूं एवं मक्का अनुसंधान संस्थान, करनाल को एक पत्र भेजा। पत्र मिलने के बाद, करनाल से दो वैज्ञानिक वाराणसी प्रकाश रघुवंशी के फार्म पर पहुंचे। रघुवंशी ने उन्हें 31 गेहूं की प्रजातियां सौंपी। शेष प्रजातियां अक्टूबर माह में बीज गोदाम खुलने पर सौंपी जाएंगी। बारिश के मौसम में बीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शेष प्रजातियों को बाद में दिया जाएगा। इन प्रजातियों में प्रमुख रूप से सूर्या 555, कुदरत अन्नपूर्णा, रघुवंशी 777, कुदरत 17, कुदरत 9 आदि शामिल हैं।

जैविक खेती का खास तरीका

रघुवंशी का जैविक खेती का तरीका भी बेहद खास है। वे बनारस के मंदिरों से मिलने वाले फूलों, मदार और धतूरा का उपयोग कर जैविक खाद तैयार करते हैं और अमृत जीवा नामक घोल का उपयोग फसलों की सुरक्षा और बीज शोधन के लिए करते हैं। उनका मानना है कि बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ग्रेडिंग और पैकिंग की व्यवस्था खुद करनी चाहिए। अपने संघर्षों के बावजूद, रघुवंशी ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा किसानों को स्वदेशी बीजों का उपयोग करने और अपने बीजों को स्वयं विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उनके बीजदान अभियान ने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई है और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। श्रीप्रकाश सिंह रघुवंशी का जीवन और कार्य अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

स्वदेशी बीजों से मिलेगी बेहतर पैदावार

रघुवंशी द्वारा विकसित गेहूं की कुदरत किस्म, जो 1995 में उनके खेत में उगाई गई थी, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इसके बाद उन्होंने गेहूं की कुदरत-7, कुदरत-9 जैसी अन्य किस्में विकसित कीं। अब तक, उन्होंने गेहूं की लगभग 80, धान की 25 और दालों की 10 और सरसों की 3 से अधिक किस्में विकसित की हैं। इसके अलावा, उन्होंने सरसों, मटर और अन्य फसलों के 200 से अधिक स्वदेशी बीज संरक्षित किए हैं। उनकी उन्नत किस्में प्रमुख कीटों और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी हैं और उनके बीज स्वादिष्ट और सुगंधित होते हैं। गेहूं की उन्नत किस्मों की प्रति एकड़ उपज 15-27 क्विंटल के बीच होती है। धान की उन्नत किस्मों की उपज 15-30 क्विंटल प्रति एकड़ और अरहर की उन्नत किस्मों की उपज 10-15 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। कुदरत-9 गेहूं और अरहर की कुदरत -3 सरकार ने पंजीकृत किया है। रघुवंशी अपने खेतों पर धान, गेहूं और अरहर सहित कई फसलों में जैविक तरीके से खेती करके अपने स्वदेशी बीजों से बंपर पैदावार ले रहे हैं। उन्होंने अपने घर पर एक बीज बैंक स्थापित किया है, जिसमें कई प्रकार के बीज संग्रहित हैं।

प्रदेश में मूंग किसानों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई

मूंग उत्पादक किसानों का अटका दो करोड़

5 अगस्त तक समर्थन मूल्य पर की गई थी मूंग खरीदी

श्योपुर जिले में अभी तक किसानों को नहीं किया भुगतान

भोपाल। जागत गांव हमार

मूंग की खरीदी बंद हुए महीने भर हो गए हैं, लेकिन अभी तक सैकड़ों किसानों को अभी तक भुगतान नहीं मिला है। जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। श्योपुर जिले में किसानों का 2 करोड़ से अधिक भुगतान बकाया है। जिले में 5 अगस्त को ही मूंग की खरीदी बंद हो गई, लेकिन इसके बाद लगभग एक पखवाड़ा बीता गया है। बाजवूद इसके 72 किसान भुगतान से वंचित हैं। जबकि नियमानुसार फसल बेचने के 5 दिन में किसान को भुगतान हो जाना चाहिए। ऐसे में अब किसान परेशान हैं। वहीं किसानों के पास परिवार चलाने का एक मात्र साधन कृषि ही है। वह इसमें महनत करता है, लागत लगाता है, फसल उगाता है और फिर फसल बेचकर परिवार चलाता है। भुगतान अभाव में कई किसान अपने बच्चों की स्कूल फ तक नहीं भर पा रहे है। किसानों ने सेसाइटी प्रबंधक के चक्कर काट रहे हैं।

332 किसानों ने बेचा 8 करोड़ का मूंग

प्रदेश सरकार ने 26 जून से 5 अगस्त तक समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की। इसके तहत जिले में 3 खरीद केंद्र बनाए गए थे। जिन पर 332 किसानों ने 9 लाख 68 हजार 910 क्विंटल मूंग बेचा। जिसके एवज में किसानों को 8 करोड़ 29 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया जाना था, लेकिन अभी तक 260 किसानों को 5 करोड़ 82 लाख रुपए का भुगतान हो पाया है। ऐसे में अभी एक सैकड़ा से अधिक किसानों को 2 करोड़ से अधिक का भुगतान अटका हुआ है।

इन केंद्रों पर हुई थी मूंग की खरीदी

सहकारी संस्था श्योपुर, सेवा सहकारी संस्था कनापुर, सेवा सहकारी संस्था सोईकलां, वृहत्ताकार सहकारी संस्था उतनवाड, सेवा सहकारी संस्था मानपुर, वृहत्ताकार सहकारी संस्था बडौदा, वृहत्ताकार सहकारी संस्था फिलोजपुरा, विपणन सेवा सहकारी संस्था कराहल, विपणन सेवा सहकारी संस्था विजयपुर पर खरीदी की गई थी।

एक सैकड़ा करीब किसानों का दो करोड़ से अधिका भुगतान शेष है, जिसके लिए प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही किसानों को भुगतान हो जाएगा।

- दिनेशचंद गुप्ता, नोडल अधिकारी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक श्योपुर

रिलायंस ने कहा-गांवों में निकलेंगी 30 हजार नौकरियां

मुकेश अंबानी बायो एनर्जी से किसानों को बनाएंगे ऊर्जादाता

» रिलायंस सोलर पीवी मॉड्यूल प्रोडक्शन शुरू करेगी

» रिलायंस न्यू एनर्जी सेगमेंट पर जोर, बड़ा मुनाफा संभावित

भोपाल। अरबपति कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस एजीएम 2024 में न्यू एनर्जी सेगमेंट को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि रिलायंस का जोर अब न्यू एनर्जी सेगमेंट पर रहेगा, क्योंकि इसमें काफी संभावनाएं हैं। मुकेश अंबानी, रिलायंस इडंस्ट्रीज के चेयरपर्सन ने कहा कि न्यू एनर्जी कारोबार में काफी मुनाफा है। यह 5 से 7 साल बाद ही ऑयल टु केमिकल बिजनेस के बराबर मुनाफा करेगा। उन्होंने बताया कि रिलायंस ने कच्छ में बंजर भूमि पट्टे पर लेकर उसमें बिजली पैदा की जाएगी। हमारा टारगेट है कि आने वाले 10 साल में 150 अरब यूनिट बिजली पैदा करेंगे। यह भारत की कुल ऊर्जा का 10 प्रतिशत है।

सोलर फोटो-वोल्टाइक का प्रोडक्शन

रिलायंस ने तय किया है कि वह सोलर फोटो-वोल्टाइक मॉड्यूल के प्रोडक्शन का काम इस साल से शुरू करेगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि हमने तय किया है कि मॉड्यूल, सेल, ग्लास, वेफर, इंगोट और पॉलीसिलिकॉन से जुड़ा एकीकृत सौर उत्पादन सुविधाओं के पहले चरण का काम अगली तिमाही तक पूरा कर लें। शुरूआत में इसकी क्षमता 10 गीगावॉट तक रहेगी। जामनगर में एकीकृत उन्नत रसायन आधारित बैटरी विनिर्माण पर काम चल रहा है। इसमें काम शुरू होने के लिए एक साल का समय लगेगा।

-साक्षात्कार | केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सामने रखा खेती-किसानी पर सरकार का रोडमैप

किसान की आय बढ़ी एमएसपी देना जायज

पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में खेती में हुए क्रांतिकारी बदलाव

-हमारे शरबती गेहूं की धूम पूरी दुनिया में है, निर्यात की संभावनाएं भी अनंत

-देश में अच्छे बीज के उत्पादन से लागत घटेगी, किसानों का प्रॉफिट बढ़ेगा

भोपाल। जागत गांव हमार

किसानों को फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देना जायज है। किसान घाटे में कब तक खेती करेगा, उनका भी परिवार है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक साक्षात्कार के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ी है। खेती-किसानी के विकास और उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की रणनीति में कई बिंदु शामिल किए गए हैं जिन पर काम किया जा रहा है। फसल विविधीकरण शुरू हो गया है, सिंचित भूमि के लिए और नए बीजों पर काम किया जा रहा है। देश दुनिया का फूड बास्केट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चावल समेत अन्य खाद्यान्न के निर्यात में बढ़ोत्तरी हो रही है। कृषि मंत्री ने कृषि और किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों का रोडमैप सामने रखा। बातचीत के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया कि मोदी सरकार ने 2016 में वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी को डबल कर देंगे, वह वादा वक्त से बहुत पीछे चल रहा है। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ी है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं की किसानों की आमदनी नहीं बढ़ाई गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में खेती में कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। हमारी जो रणनीति है वह किसानों की आमदनी बढ़ाने की है। उसके साथ साथ देश की खाद्य सुरक्षा पक्की करने की है।

भारत में दुनिया का फूड बास्केट बनने की क्षमता – कृषि मंत्री ने कहा कि आज हमारी आबादी 140 करोड़ है और यह बढ़कर 2047 तक 160 करोड़ हो जाएगी, तो खाने पीने की चीजों का उपयोग ज्यादा होगा तो खपत भी ज्यादा होगी। उस नजरिए से हमें देश की जरूरत को भी पूरा करना है तो वहीं किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी रहें और हम देश की खाद्य जरूरतों को भी पूरा करें। कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी का और हमारा सपना है कि भारत में क्षमता है दुनिया का फूड बास्केट बनने की। हम न केवल अपनी बल्कि दुनिया की खाद्य जरूरत को भी पूरा करें, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकेले अगर मैं चावल की बात करूं तो 40,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट इस साल किया गया है। हमारे शरबती गेहूं की धूम पूरी दुनिया में है। निर्यात की संभावनाएं अनंत हैं।

सरकार का बिंदुओं पर फोकस

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की कृषि और किसानों को लेकर रणनीति के तहत कुछ बिंदुओं पर अधिक फोकस करना है, जिनमें शामिल हैं-फसलों का उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन का ठीक दाम देना और लाभकारी मूल्य देना, जलवायु बदलाव को देखते हुए प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान की भरपाई करना, खेती का विविधीकरण और वैल्यू एड करना। इसके अलावा सरकार की प्रमुखता में धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाकर रखने के लिए नेचुरल फार्मिंग पर फोकस करना है। ताकि 50 साल बाद भी धरती उपज देती रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि इन बिंदुओं पर सरकार काम कर रही है। यह सब अचानक से नहीं हो जाएगा, धीरे-धीरे इस पर काम किया जा रहा है।

सिंचाई व्यवस्था पर सरकार का जोर

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसके अलावा कुछ जरूरी बाते हैं जिन पर सरकार का फोकस है। उन्होंने कहा कि सिंचाई के रकबे को बढ़ाने की आज भी बहुत गुंजाइश है। मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बना तो सिंचित जमीन का रकबा केवल 750 लाख हेक्टेयर था हम उसे बढ़ाकर 50 लाख हेक्टेयर पर ले गए। अभी जो कम चल रहा है उससे 70 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित रकबा हो जाएगा। अब तो केन-बेतवा नदी रिवरलिंकिंग प्रोजेक्ट स्वीकृत कर दिया गया है तो 20 लाख एकड़ क्षेत्र तो इससे सींचा जा सकेगा। अभी भी कई नदियां हैं, जिनमें खूब पानी है उनके पानी को वहां ले जाया जा सकता है जहां पानी की कमी है।

नए बीजों पर 5 हजार लैब में चल रहा काम

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि बीज उत्पादन बढ़ाना हमारी रणनीति का हिस्सा है। बीज उत्पादन के लिए हमारे पास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जिसके तहत 5,500 वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में काम कर रहे हैं। पिछले दिनों पीएम मोदी ने 65 फसलों की 109 किस्मों के नए बीज किसानों के लिए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए बाजरे का एक बीज बनाया है, जिसमें 70 दिन में फसल तैयार हो जाएगी। आमतौर पर बाजारा 110 से लेकर 120 दिन के बीच में आता है। नए बीजों से किसानों का समय बचेगा, जल्दी कटेगा और दूसरी फसल के लिए भी गुंजाइश बनेगी। धान की एक वैरायटी विकसित की है जिसमें 30 फीसदी पानी कम लगेगा। इस किस्म को रोपाई की बजाय सीधे बोया जा सकेगा।

तीन गुना तेजी से काम करेगा कृषि मंत्रालय

कृषि मंत्री ने कहा कि फसलों की लागत घटाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। आज किसान यूरिया हाथ से फेंकता है तो कहीं ज्यादा यूरिया गिरती है कहीं कम। लेकिन, अब हम इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो लागत कम आएगी। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा कि वह तीन गुना ज्यादा तेजी से काम करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग भी तीन गुना तेजी से काम करेगा।

किसान को एमएसपी देना जरूरी

शिवराज ने कहा कि अच्छे बीज उत्पादन से लागत घटेगी, किसान का प्रॉफिट बढ़ेगा। खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। किसान फायदे की खेती करते रहें। उन्होंने कहा कि अभी एमएसपी देना निश्चित तौर पर जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसान घाटे की खेती कैसे करेगा। किसान को पेट भरना है, उनके बच्चों की पढ़ाई है, बेटी की शादी करना है और दूसरे काम करना है। केंद्र सरकार फसल की लागत पर 50 फीसदी प्रॉफिट जोड़कर एमएसपी तय कर रही है। एमएसपी देने का फैसला उत्पादन की लागत पर 50 फीसदी केंद्र की सरकार ने किया है, यह जायज है। हमें उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। किसानों को क्वालिटी के अनुकूल उत्पादन के लिए जागरूक करना होगा।

अब खेती का पैटर्न बदल रहा

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती का पैटर्न अब बदल रहा है। विविधीकरण के चलते हमारा हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। फसल विविधीकरण एकदम नहीं होगा। धीरे धीरे बदलाव आता है। हम उसको कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डायवर्सिफिकेशन के लिए सुनियोजित रणनीति पर काम किया जा रहा है। बहुफसली परंपरा को अपनाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। खेती की विकास गति को लेकर कृषि मंत्री ने बताया कि हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 4.6 फीसदी है।

कांग्रेस ने एमएसपी देने से किया इंकार

कांग्रेस के एमएसपी गारंटी देने को मुद्दा बनाने को लकेर कृषि मंत्री ने कहा कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 1947 से लेकर 1950 के बीच लाल किले से अपने संबोधन में केवल एक बार किसान का नाम लिया और उसके बाद 1951 से 1958 तक कभी किसान का नाम तक नहीं लिया। कृषि मंत्री ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। यह किसान को केवल वोट बैंक मानते हैं। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि ये कांग्रेस थी जिसने कैबिनेट नोट में एमएसपी 50 फीसदी लागत पर जोड़कर देना चाहिए, उससे इनकार कर दिया था और कहा था कि इससे बाजार बिगड़ जाएगा।

-कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया एलान, किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि जीवन दाता

मोदी सरकार ने किसानों के लिए तय की छह प्राथमिकताएं

इधर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की सेवा के समान, ये सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि जीवन दाता हैं। जीडीपी में 18 प्रतिशत सीधे कृषि का योगदान हैं, इसके अलावा किसान फ्रीज भी खरीदता है, कूलर भी खरीदता है, जिससे उसका योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में भी होता है। किसान सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। कृषि मंत्री बनने के बाद मैंने सभी प्रधानमंत्रियों के भाषण पढ़े, लेकिन अफसोस कि किसी भी प्रधानमंत्री ने लालकिले की प्राचीर से किसानों का जिक्र नहीं किया। देश के पहले पीएम जवाहर लाल नेहरू का बहुत आदर करता हूं, लेकिन अपने तीन कार्यकाल में एक बार भी लालकिले से उन्होंने किसानों का जिक्र नहीं किया। जबकि पीएम नरेंद्र मोदी कृषि के प्रति समर्पित हैं। किसान उनकी प्राथमिकता हैं।

गिनाईं केंद्र की प्राथमिकताएं

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि को लेकर सरकार की छह प्राथमिकताएं गिनाईं, जो कि इस प्रकार हैं-खाघ सुरक्षा मजबूत करना, उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाना। उत्पादन की लागत घटाना। उत्पादन की सही कीमत देना। प्राकृतिक आपदा के दौरान किसानों के नुकसान की करना। फसलों का विविधिकरण करना। आने वाली पीढ़ी के लिए धरती सुरक्षित रखना।

तैयार की 106 तरह की उन्नत फसल

शिवराज सिंह ने मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए 106 तरह की उन्नत फसलें तैयार की हैं, जिनमें कई फसलें कम दिनों में तैयार हो जाती हैं। साथ ही नई-नई पद्धित तैयार करना और किसानों तक पहुंचाना। हमारा मिशन लैंड टू लैब का रोडमैप तैयार करना है। किसान लैंड में काम करता है और वैज्ञानिक लैब में दोनों की दूसरी तय करने पर हमारी सरकार काम कर रही है। मोदी सरकार उपलब्धियां गिनाते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि 2014 तक जो एमएसपी तय होती थी। आज मोदी सरकार उससे दोगुनी एमएसपी दे रही है।

उन्नत बीजों का प्रयोग, फसल में बढ़ जाता है 20 प्रतिशत उत्पादन

» डॉ. चंचल भार्गव
» डॉ. रिया ठाकुर
जनेकृविवि, कृषि विज्ञान केन्द्र, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश

उन्नत बीज वह होता है, जिसमें आनुवांशिक शुद्धता शत-प्रतिशत हो,अन्य फसल एवं खरपतवार के बीजों से रहित हो, रोग व कीट के प्रभाव से मुक्त हो, अंकुरण क्षमता उच्च कोटि की हो, खेत में जमाव और अन्ततः उपज अच्छी हो। उन्नत बीज वह होता है जो रोगों के प्रतिरोधक हो और प्रदेश की जलवायु के अनुसार हो। कई बार किसान ऐसे बीजों की बुवाई कर देते हैं, जिससे उत्पादन घट जाता है और किसान को उम्मीद के अनुसार लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए प्रामाणिक उन्नत बीजों का ही उपयोग करना चाहिए। उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज के प्रयोग से ही लगभग 20 प्रतिशत उत्पादकता/उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।

पौधे का वह भाग, जिसमें भ्रूण अवस्थित होता है और इसकी अंकुरण क्षमता, आनुवंशिक एवं भौतिक शुद्धता तथा नमी आदि मानकों के अनुरूप होने के साथ ही बीजजनित रोगों से मुक्त होता है-उसको बीज कहा जाता है। बुवाई के पूर्व कृषक भाई किस्मों के चयन व अन्य समसामयिक सलाह हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकतें है। इस दिशा में कृषि विज्ञान केन्द्र तत्परता से निरंतर कार्य कर रहे हैं। किसानों को बीज का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत है।

कृषकों को बुवाई के पूर्व बीज चयन हेतु निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए-

- जिस बीज में आनुवंशिक तथा प्रजातीय शुद्धता हो अर्थात् बीज में किस्म के अनुरूप आकार, प्रकार, रंग, रूप तथा भार के लक्षण हों, अच्छा बीज माना जाता है।
- फसल सघनता बढ़ाने कम अवधि में पकने वाली व अधिक पैदावार देने वाली फसलों के बीज उपयोग करना चाहिए।
- प्रतिवर्ष संकर किस्मों के नए बीज प्रयोग करने चाहिए। पिछले वर्षों के बीज उपयोग से पैदावार कम मिलती है।
- चयन किए गए बीज किस्मों को लगातार तीन चार वर्ष के बाद बुवाई के काम में नहीं लेना चाहिए।
- बीज शुद्ध एवं साफ होना चाहिए तथा किसी फसल या किस्म के बीज में अन्य फसलों या किस्मों के बीज का मिश्रण नहीं होना चाहिए। शुद्ध एवं स्वस्थ बीज में अंकुरण क्षमता के साथ-साथ प्रारम्भिक बढ़ाव की क्षमता अधिक होती है।
- बीज का रोग रहित होना अनिवार्य है। अत: ऐसा बीज उपयोग करना चाहिए, जिसमें पूर्व में कोई रोग न लगा हो। रोगी बीज में रोग प्रतिरोधी क्षमता कम होने से या तो वह अंकुरित नहीं होता अथवा अंकुरण के बाद मर जाता है।
- लगभग हर बीज के दाने, वजन एवं आकार में एक समान होना चाहिए। शीघ्र एवं एक समान अंकुरण हेतु अच्छा बीज ओज होना आवश्यक है। बीज ओज से तात्पर्य बीज की उस प्राकृतिक और शरीर क्रियात्मक स्वस्थता से है, जिसमें तीव्रता से एक समान अंकुरण होता है और पौधा विकसित होता है।
- बीज की अंकुरण क्षमता की जांच कर लेना चाहिए। अंकुरण क्षमता के अनुसार ही इकाई क्षेत्र में निश्चित पौध संख्या को बरकरार रखा जा सकता है अन्यथा उपचार विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- बीज के दाने पूर्ण और परिपक्व होना चाहिए।
- बीज में आर्द्रता मात्रा जब निर्धारित स्तर 10-15: से अधिक होती है तो भंडारण के दौरान बीज की अंकुरण क्षमता व बीज गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

बीज की अंकुरण क्षमता का आंकलन: बीज की अंकुरण क्षमता की शीघ्र जानकारी प्राप्त करने हेतु बीज को रातभर पानी में भिगो देते हैं। सुबह बीजों को 2-3-5 टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड के 1: घोल में 2-4 घंटों तक डुबोते हैं। जीवित बीजों में श्वसन होता है तथा मरे हुए बीज श्वसन नहीं कर सकते हैं। रंगहीन टेट्राजोलियम, भ्रूण के एन्जाइम के सम्पर्क में आकर भ्रूण की जीवित कोशिकाओं को लाल रंग में बदल देता है। इस टेस्ट को टेट्राजोलियम या टी टेस्ट कहते हैं। कुछ बीजों को गिनकर जमीन के एक कोने में अच्छी तरह से बो देना चाहिए अंकुरण पश्चात्

अंकुरित पौधों को गिन लेना चाहिए फिर निम्न सूत्र प्रयोग करके अंकुरण प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है।

उन्नत बीज आप भी पैदा कर सकते हैं : उन्नत सुधरे बीजों की सुलभ उपलब्धि हेतु कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग, मप्र राज्य बीज निगम व राष्ट्रीय बीज निगम तत्परता से कार्य कर रहे हैं। किन्तु प्रयासों के पश्चात् भी कई बार कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इन परिस्थितियों में कृषकों को अपने प्रक्षेत्र पर स्वयं बीजोत्पादन करना चाहिए। बीजोत्पादन हेतु कृषकों को निम्न तकनीकी जानकारी होना चाहिए।

आधार बीज का उपयोग: बीजोत्पादन हेतु आधार बीज अधिक उपयुक्त होता है। प्रजनक बीज से जो बीज उत्पादित किया जाता है उसे आधार बीज कहते हैं। यह बीज इस प्रकार उत्पन्न किया जाता है कि विशेष मानकों के अनुसार इसमें अनुवांशिक गुण और शुद्धता बनी रहती है।

खेत की तैयारी: जिस खेत में बीज उत्पादन कार्यक्रम लेना है उसको गर्मी में अच्छी तरह से जुताई कर बिखरना चाहिए ताकि खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो जाए तथा गर्मी से जमीन में छिपे कीट नष्ट हो जाएं। पौधों को समुचित वृद्धि हेतु भूमि की भौतिक दशा, भूपरिष्करण क्रिया द्वारा सुधारना अति आवश्यक है। अच्छी तरह से भुरभुरी मिट्टी में समुचित जल तथा वायु का शोषण संचार होता रहता है। अत: बीजोत्पादन वाले खेत की उचित जुताई वबखरनी कर खेत को समतल रखना चाहिए।

गोबर की अच्छी पकी खाद का उपयोग करें: गोबर व कम्पोस्ट खाद उपयोग में सावधानी रखना आवश्यक है। यह ध्यान रखें कि खाद पूर्ण रूप से पकी व पची होना चाहिए अन्यथा बाद में खरपतवार के बीज आ जायेंगे, जिसमें फल विपरीत रूप से प्रभावित होगी खाद के साथ नुकसानदायक जीवाणु व दीमक आदि आने की संभावना भी बनी रहती है। अत: भूमि में इमिडाक्लोप्रिड अथवा फिब्रोनिल बोनी पूर्व मिट्टी में मिला देना चाहिए।

बीजोपचार एक जरूरी आवश्यकता है: कुछ बीजजन्य रोग जैसे बीज सड़न, जड़ सड़न, पदगलन पत्तों का धब्बा झुलसन तथा कण्डुआ आदि रोग बीज के द्वारा ही फैलकर फसल वृद्धि तथा उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। इन फफूंदों से बीज को सुरक्षित करने हेतु फफूंदनाशक औषधियों से बीजोपचार करना बहुत जरूरी है। यह गीले व सूखे दोनों तरीकों से किया जा सकता है। सूखी विधि में उपयुक्त बीज मात्रा तथा फफूंदनाशक दवा की सिफारिश मात्रा सोड ट्रीटिंग ड्रम में डालकर 10 मिनिट तक घुमाने से दवा बीजों पर परत रूप में चढ़ जाती है फिर यह बीज बुवाई के लिए उपयोग करें। इस ड्रम की अनुपलब्धता में घड़े का उपयोग भी कर सकते हैं। जबकि गोली विधि में फफूंद नाशक दवा का पानी में घोल बनाकर सिफारिश बीज मात्रा को इस घोल में 10 मिनट डुबोकर निकालें और फिर बोनी करें।

विजातीय पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें: बीज की शुद्धता बनाए रखने हेतु खेत में समय-समय पर भ्रमण के दौरान फसल में उगते हुए विजातीय पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें।

समय-समय पर निंदाई गुड़ाई करें: कृषकों को खेत का नियमित निंदाई, गुड़ाई करते रहना चाहिए। जिससे कि अवांछित पौध नष्ट हो जाएगे साथ ही साथ भूमि में जड़ों के पास उचित वायु संचार होता है। इससे भूमि में उपस्थित जल कोशिकाएं भी टूट जाती हैं फलस्वरूप भूमि में अनावश्यक जल वाष्पन भी रुकता है।

आवश्यक पौध संरक्षण उपाय अपनाएं: अधिकांशत: कृषक कीट व्याधियों की रोकथाम हेतु पूर्व से ही सतर्क नहीं रहते हैं। इनका प्रकोप होने के पश्चात् उनको रोकथाम हेतु उपाय ढूंढते हैं। तब तक बीज रोग ग्रस्त या कीटों द्वारा प्रभावित हो चुका होता है। इससे प्राप्त बीज की गुणवत्ता में प्रतिकूल रूप असर होता है। अत: कृषक बीजोत्पादन में कीट व्याधियों का विशेष ध्यान रखें। जैसे ही इनका प्रारम्भिक प्रकोप दिखे तब तुरन्त ही आवश्यक पौध संरक्षण उपाय अपनाते हुए उन्हें नियंत्रित करें।

कटाई पर ध्यान देना बहुत आवश्यक: फसल में बीज जब पूर्ण रूपेण परिपक्व हो जाए तभी सही समय व उचित नमी स्तर पर कटाई करें उसके पहिले या बाद में नहीं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि कटाई में पौधे जड़ सहित न उखड़ आए, वर्ना बीजों में मिट्टी भी आ जाती है जिस पर बाद में सफाई हेतु अनावश्यक व्यय होता है।

बरसात के मौसम में पशु प्रबंधन एवं सावधानियां

» डॉ. सोनू कुमार यादव
» डॉ. अंजनी कुमार मिश्रा
» डॉ. प्रमोद शर्मा
» डॉ. भावना अहरवाल
» डॉ. संकेत पाठक
(पीएच.डी शोधार्थी) (प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष) (सहायक प्राध्यापक) (सहायक प्राध्यापक) (पीएच.डी शोधार्थी)
पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय रीवा, मध्यप्रदेश

भारत विभिन्नताओं का देश रहा है। कई तरह की संस्कृतियां पाई जाती हैं। संस्कृतियों की तरह ही भारत में कई तरह की ऋतुएं हैं। ऋतुओं को 6 भागों में बांटा गया है। वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु। हर ऋतु का पशुओं पर एक अलग ही प्रभाव देखने को मिलता है। पशुओं को वर्षा ऋतु के खराब मौसम से बचाने की आवश्यकता होती है, ताकि पशुओं से प्राप्त पदार्थों के उत्पादन के स्तर को बनाए रखा जा सके एवं पशुओं से ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित किया जा सके।

बरसात के मौसम में पशुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस मौसम में तापमान में होने वाले उतार चढ़ाव की वजह से पशुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हैं। अगर समय रहते सावधानियां बरती गाई तो पशूओं को कई प्रकार की बिमारियों से बचाया जा सकता है इसी मौसम के दौरान परजीवियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि देखने को भी मिलती है जिनके द्वारा पशुओं को प्रोटोजीवन एवम् पेरासिटिक रोग हो जाते हैं।

बरसात के समय वातावरण में आद्रता की अधिकता होने के कारण पशु तनाव महसूस करने लगते हैं पशु की पाचन प्रक्रिया के साथ-साथ उसकी आन्तरिक रोग प्रतिरोधक छमता पर भी असर पड़ता है परिणामस्वरूप पशु अनेक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। अत्यधिक आद्रता के कारण। बरसात के मौसम में पशुओं में गलघोंटू मुहपका खुरपका थनैला रोग वा लंगड़ी बुखार नामक बीमरिया हो सकती हैं। जिसके कारण पशु पहले तो खाना पीना कम कर देता है बाद में काफी कामजोर हो जाता है या कई बार तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। इन रोगों के प्रकोप से पशु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अत: अपने पशुओं को इन बिमारियों से बचाने के लिए बरसात से पहले टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए।

बरसात के मौसम में ध्यान देने योग्य बातें: बारिश के पहले पशुओं के पशुशाला की छत की मरम्मत कर दें, जिससे बारिश का पानी ना टपके व बरसात के मौसम में पशुशाला में पानी का जल जमाव न हो। इस मौसम में पशुओं के साथ साथ पशुशाला की साफ सफाई का खास खयाल रखें एवं पानी को एक जगह पर एकत्रित नही होने दें जिससे मच्छर पनप न सकें और परजीवी संक्रमण को रोका जा सकें। बरसात के मौसम में पशुशाला को दिन में एक बार फिनाइल के घोल से अवश्य साफ करें, जिससे बिमारी फैलाने वाले बैक्टीरया व सूक्षमजीवी कम हो सकें।

बारिश के मौसम में पशुओं को बाहर चरने के लिए नहीं भेजें क्योंकि बारिश के मौसम में गीली घास पर कई तरह के कीड़े होते हैं जो पशुओं के पेट में चले जाते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचा सकते है। पशु को खेतों के समीप गड्ढे या जोहड़ का पानी पिलाने से परहेज करें क्योंकि इस दौरान किसान खेतों में खरपतवार एवं कीटनाशक का इस्तेमाल करते है जो कि रिसकर इनमें आ जाता है। कोशिश करें की पशु को बाल्टी से साफ एवं ताजा पानी पिलाएं ।

दाने का भंडारण नमी रहित स्थान पर करें और ध्यान दें कि इस मौसम में दाने को 15 दिन से अधिक भंडारण न करें।

दुधारू पशुओं का दूध निकालने के बाद थनों को लाल दवा से अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए व बाद में सूखे कपडे से पोछना चाहिए

दूध निकालने के बाद आधे घंटे तक पशुओं को नहीं बैठने देना चाहिए क्योंकी इस समय थनो के छिद्र खुले रहतें है जिससे पशुओं में थनेला रोग होने की संभावना अधिक होती है

पशुओं में ब्रह्म परजीवियों का प्रकोप- बारिश के मौसम में प्राय: यह देखा गया है की ब्रह्म परजीवियों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि हो जाती है। जिससे पशुओं को कई प्रकार की शारीरिक व मानसिक व्याधियों का सामना करना पडता हैं। पशुओं में परजीवी प्राय: दो प्रकार के पाए जाते हैं अन्त: परजीवी- जैसे पेट के कीड़े, कृमि आदि ब्रह्म परजीवी - चीचड़ मेंज, जू आदि रोगग्रसित पशुओं में सुस्ती, कमजोरी, अनीमिया (खून की कमी) एवं दूध में कमी देखने को मिलती है। पशु को पाचन प्रक्रिया में शिकायत रहती है। जिससे पेट में दर्द और पतला गोबर आता है। वर्षा ऋतु के दौरान पशुओं में अक्सर खाज-खुजली की शिकायत होती है एवं शरीर में लाल दाने आ जाते हैं इसका मुख्य कारण पशुशाला में गंदगी का होना है। इस रोग में पशु की त्वचा पर अत्यंत खुजलाहट होती है, जिसकी वजह से त्वचा मोटी होकर मुरझा जाती है एवं पशु के खुजली करने पर त्वचा छिल जाती है और उस जगह के सारे बाल झड़ जाते हैं। कभी-कभी इन जगह पर जीवाणुओं के संक्रमण से दुर्गन्ध भी आती है। पशुचिकित्सक की सलाह से पशुओं को उनके वजन के अनुसार परजीवीनाशक दवा नियमित रूप से पिलानी चाहिए।

जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे की कगार पर पहुंची टारेंटयुला की प्रजाति

दक्षिण-पूर्वी एरिजोना के चिरिकाहुआ पर्वतों से टारेंटुला मकड़ी की एक नई प्रजाति, एफोनोपेल्मा जैकोबी की खोज की गई है। इस छोटी, काले और भूरे रंग की टारेंटुला प्रजाति के पेट पर लाल बाल होते हैं और इसे चिरिकाहुआ पर्वतों के ऊंचे-ऊंचे इलाकों में देखा जा सकता है, जहां यह कड़ाके की ठंड में भी जीवित रहती है।

अक्सर हम पृथ्वी के कोनों-कोनों से नई प्रजातियों की खोज के बारे में सुनते हैं, लेकिन इन मकड़ियों के रहने वाले इलाकों तक पहुंच पाना कठिन होता है।

धरती पर मानवजनित कारणों से विलुप्ति संकट के बीच, हम अपनी धरती की जैव विविधता के बारे में कितना कम जानते हैं, यहां तक कि टारेंटयुला जैसे अनोखे और करिश्माई जीवों के बारे में भी बहुत कम जानकारी है।

चिरिकाहुआ, जो अपनी असाधारण जैव विविधता और ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध हैं, मैड्रियन द्वीपसमूह का हिस्सा हैं, जहां घने जंगलों वाले पवज्त श्रृंखलाएं है जो दक्षिण-पश्चिमी अमेरिका में कोलोराडो पठार और रॉकी पवज्त और उत्तर-पश्चिमी मैक्सिको में सिएरा मैड्रे ऑक्सिडेंटल के बीच कॉर्डिलेरन तक फैला हुआ है।

ये पर्वतीय जंगल जो कम ऊंचाई वाले रेगिस्तानों और शुष्क घास के मैदानों दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं, जिसके कारण यहां कई छोटी-सीमा वाली स्थानीय प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है। यहां अमेरिका के किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में जैव विविधता अधिक पाई जाती है।

जिन जंगलों में ये टारेंटुला रहते हैं, वे कई कारणों से खतरे में हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण जलवायु में बदलाव है। स्काई आइलैंड क्षेत्र में हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि अगले कई दशकों में ये जंगल पहाड़ों से गायब हो सकते हैं क्योंकि बढ़ता तापमान और बारिश की अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है। इन ठंडे और अधिक नमी वाले पर्वत शिखरों में रहने वाले जीव - जैसे कि ये मकड़ियां विलुप्त हो जाएंगी क्योंकि इनके रहने के अनुकूल आवास गायब हो जाएंगे।

शोधकर्ता ने शोध के हवाले से कहा कि इन नाजुक आवासों को सैन साइमन वैली और पोर्टल क्षेत्रों में बढ़ते बाहरी विकास, विनाशकारी मनोरंजक गतिविधियों और जंगल की आग से भी खतरा है। इसके अलावा कुछ और चिंताएं भी हैं जिनमें टारेंटयुलाओं का उनकी दुर्लभता, आकर्षक रंग और सरल स्वभाव के कारण विदेशी पालतू व्यापार के लिए इनका शोषण किया जा सकता है। इस प्रजाति के लिए खतरों और इसके संरक्षण के उपाय करते समय इन्हें अनैतिक रूप से जमा करने वालों के कारण इन मकड़ियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए।

नई फसल से पहले ही भाव एमएसपी से नीचे, सोयाबीन के भाव में गिरावट से किसानों की बढ़ी चिंता

सोयाबीन की फसल बन रही घाटे का सौदा

झाबुआ। जागत गांव हमार

पिछले कई वर्षों से सरकार की गलत नीतियों के कारण सोयाबीन उत्पादक किसानों को काफी निराश होना पड़ रहा है। आलम यह है कि 10 वर्षों पहले सोयाबीन जिस भाव से बिक रहा था। उससे भी कम रेट में अब सोयाबीन के भाव चल रहे हैं। बाजार से लेकर मंडियों में सोयाबीन समर्थन मूल्य से भी नीचे बिक रहा है। सोयाबीन का सीजन डेढ़ माह बाद शुरू होने वाला है। इसके पहले सोयाबीन के भाव को लेकर किसानों में आक्रोश व्याप्त होने लगा है। फसल का वाजिब दाम नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश है। गौरतलब है की क्षेत्र के किसानों मि मुख्य सोयाबीन है। खरीफ सीजन में यहां सबसे अधिक सोयाबीन की खेती होती है। इसीलिए इसे पीला सोने के नाम से जाना जाता है। खरीफ सीजन में किसानों के द्वारा काफी मात्रा में सोयाबीन की मुख्य फसल बोई जाती है। सोयाबीन का वाजिब दाम दिलवाने की मांग करते हुए किसानों ने अब सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन का असर दिखाई देने लगा है। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा महेंद्र हामड ने बताया कि सोयाबीन के भाव बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों ने आवाज उठाई है। जिसका भारतीय किसान यूनियन ग्रामीण स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक ज्ञापन देने का अभियान चलाएंगे।

कम दाम पर बिक रहा सोयाबीन

ग्राम बोडायता के किसान अर्जुन पाटीदार ने बताया कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4892 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। लेकिन इस भाव से बहुत कम दाम पर सोयाबीन मंडियों और व्यापारियों द्वारा खरीदा जा रहा है। जिससे किसानों को लगभग एक हजार से तेरह सौ रुपए का घाटा हो रहा है। जबकि दूसरी ओर डेड माह बाद दिन नई सोयाबीन आने वाली है। मंडियों में 4000 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को दाम मिल रहे हैं। इसमें किसानों को लागत खर्च निकलना भी मुश्किल जाएगा।

सोशल मीडिया पर कैंपेन

भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष ईश्वर पाटीदार ने बताया कि सरकार की गलत नीति के कारण सोयाबीन के भाव नहीं बड़े हैं। वहीं किसानों द्वारा जो खेती किसानी में वस्तुएं इस्तेमाल की जाती है। उनके दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है। खाद, दवाई मजदूरी सारी चीजों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। परंतु किसानों को उनकी फसल के वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं। किसान नेताओं ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए किसान अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं। अब देखना है कि सरकार किसानों की मांगों को कितना गंभीरता से लेती है।

सप्ताह भर चलेगा ज्ञापन का दौर

सोयाबीन के भाव को लेकर सोशल मीडिया व्हाट्सएप और फेसबुक पर पोस्ट वायरल हो रहे हैं। इनमें किसानों द्वारा मांग की जा रही है कि सोयाबीन के भाव बढ़ाए जाएं। भारतीय किसान संघ के जिला महामंत्री जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि अभी सोशल मीडिया पर सोयाबीन के भाव को लेकर सरकार तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। एक सितंबर से सात सितंबर तक सप्ताह भर तक ग्राम पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक ज्ञापन दिए जाएंगे। उसके बाद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो यह मुद्दा आंदोलन का रूप अख्तियार कर लेगा।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने फसलों के बुवाई आंकड़े जारी किए

उड़द और मूंग की बोवनी का दो लाख हेक्टेयर तक बढ़ा रकबा

-उड़द और मूंग की बुवाई पर मेहरबान हुए किसान

भोपाल। जागत गांव हमार

खरीफ सीजन में दालों की बंपर बोवनी दर्ज की गई है। इस बार किसानों ने उड़द दाल और मूंग दाल की बोवनी पर खास रुचि दिखाई है। यही वजह है कि दोनों दालों के रकबे में 7 दिन में 2 लाख हेक्टेयर के करीब रकबा बढ़ गया है। इस तरह 27 अगस्त तक कुल दालों का रकबा बढ़कर 123 लाख हेक्टेयर हो गया। बीते सीजन में दाल की बुवाई 115 लाख हेक्टेयर में हुई थी। एक्सपर्ट का कहना है कि उड़द और मूंग के एमएसपी में बढ़ोत्तरी दोनों दालों की अधिक बोवनी की बड़ी वजह बनकर उभरी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने खरीफ सीजन की फसलों के बोवनी के आंकड़े जारी कर दिए हैं। आंकड़ों के अनुसार दालों में उड़द और मूंग दाल की बुवाई का रकबा बढ़ा है। मोथबीन दाल, कुल्थी दाल और अन्य दालों की कैटेगरी के रकबे में भी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।

मूंग का रकबा चार लाख हेक्टेयर बढ़ा

बुवाई के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि किसानों ने उड़द और मूंग दाल पर खास रुचि दिखाई है। उड़द दाल का रकबा बढ़कर 29.04 लाख हेक्टेयर हो गया है। हालांकि, बीते साल समान अवधि में 30.81 लाख हेक्टेयर में बुवाई की तुलना में इस बार रकबा कम है। इसी तरह मूंग दाल का रकबा 34.07 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि बीते साल समान सीजन में 30.57 लाख हेक्टेयर बुवाई की गई थी। इस सीजन मूंग दाल का रकबा 4 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है।

7 दिन में बढ़ा उड़द-मूंग का रकबा

20 अगस्त को बुवाई आंकड़े जारी किए गए थे, जिसके अनुसार उड़द दाल का रकबा 28.33 लाख हेक्टेयर था। जबकि, मूंग दाल का रकबा 33.24 लाख हेक्टेयर था। इस तरह देखें तो बीते 7 दिन के दौरान किसानों ने जमकर मूंग और उड़द की बुवाई की है। 7 दिनों के बुवाई आंकड़ों से तुलना करें तो दोनों दालों का रकबा मिलाकर करीब 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक बुवाई की गई है।

इसलिए बढ़ा रकबा

उड़द और मूंग दाल की बंपर बुवाई के पीछे कई वजहों में एमएसपी कीमतों में बढ़ोत्तरी को माना जा रहा है। जबकि, सरकार की ओर से सभी दालों की 100 फीसदी खरीद एमएसपी पर करने की घोषणा भी बड़ी वजह बनी है। इसके अलावा खरीफ सीजन से पहले केंद्र सरकार के दालों में आत्मनिर्भर बनने के अभियान का असर भी बुवाई आंकड़ों में दिखा है। बता दें कि खरीफ सीजन 2024-25 के लिए उड़द दाल के एमएसपी में 450 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई है। उड़द दाल का एमएसपी 7400 रुपये प्रति क्विंटल है। इसी तरह मूंग दाल के एमएसपी में बढ़ोत्तरी करके 8,682 रुपए प्रति क्विंटल की गई है।

कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा बकरी कृमिनाशी शिविर का आयोजन

बकरी पालन में अधिक लाभ के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन सबसे जरूरी-डॉ. सिंह

लहार। जागत गांव हमर

कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रथम पंक्ति प्रदर्शन (पशुपालन) के तहत-लहार क्षेत्र के गांव-काथा में बकरी कृमिनाशी शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गांव के बकरी पालकों की 130 से अधिक बकरियों को लिवरफ्लूक से बचाव के लिए कृमिनाशक दवा पिलाई गई। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि भिंड जिले में गरीब और भूमिहीन किसानों द्वारा बकरी पालन व्यवसाय बड़े पैमाने पर किया जाता है। जिले के पशुधन में लगभग 44 प्रतिशत आबादी सिर्फ बकरियों की ही है। स्थानीय बाजार से लेकर पूरे देश और विश्व में बकरा मास की सबसे ज्यादा मांग है। इसी प्रकार से बकरी के दूध में पाए जाने वाले औषधि लाभ के चलते इसकी मांग आज तेजी से बढ़ी है। डेंगू, लिवर आदि कई बीमारियों में बकरी के दूध की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। बकरी आज एटीएम का काम कर रही है। बावजूद इसके बकरी पालक बकरी पालन में बहुत अच्छा मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। इसके पीछे बकरियों का स्वास्थ्य अच्छा न रहना प्रमुख वजह है। जिसके चलते उनका विकास, दुग्ध उत्पादन और मांस में अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती है।

गांव में शिविर लगाकर बकरियों को दवा पिलाई

डॉ. एसपी सिंह द्वारा बताया कि स्वास्थ्य अच्छा न रहने के पीछे की प्रमुख वजहों में बकरियों के अंदर पाए जाने वाले अंत: परजीवी लिवरफ्लूक एवं पेट के कीड़े एक प्रमुख वजह हैं। जिनका समाधान तीन माह के नियमित अंतराल पर बकरियों के शरीर भार के अनुसार कृमिनाशक दवायें देकर आसानी से किया जा सकता है। इसी क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र लहार द्वारा बकरी पालकों में जागरूकता पैदा करने के लिए लहार क्षेत्र के काथा गांव में बकरी कृमिनाशक अभियान के तहत-गांव में शिविर लगाकर बकरियों को दवा पिलाई गई। शिविर के दौरान गांव की स्वयं सहायता समूह की रचना दिवाकर और एसआरएफ दीपेंद्र शर्मा द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।

जैविक और रासायनिक विधियों का क्रमिक उपयोग और महत्ता के बारे में बताया

फसलों में कीट-रोग नियंत्रण के लिए एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन तकनीक अपनाएंः कटियार

शिवपुरी। जागत गांव हमार

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र मुरैना द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी में दो दिवसीय आईपीएम ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. पुनीत कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी, अतिथि यूएस तोमर उपसंचालक कृषि शिवपुरी और केन्द्र के प्रभारी अधिकारी सुनीत कुमार कटियार द्वारा द्वीप प्रज्जवलित कर किया गया। केन्द्र के प्रभारी अधिकारी सुनीत कटियार द्वारा आईपीएम इसके विभिन्न तकनीक जैसे सस्य, यांत्रिक, जैविक और रासायनिक विधियों का क्रमिक उपयोग और महत्ता के बारे में बताया। आईपीएम के महत्व, आईपीएम सिद्वांत एवं उसके विभिन्न आयामों सस्य, यांत्रिक जैसे येलो स्टिकी, ब्लू स्टिकी, फेरोमैन ट्रैप, फलमक्खी जाल, विशिष्ट ट्रैप, ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार के उपयोग के बारे में और जैविक विधि, नीम आधारित एवं अन्य वानस्पतिक कीटनाशक और रासायनिक आयामों के इस्तेमाल के विषय में विस्तार से बताया गया। उन्होंने कहा किसान फसलों में रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं जिससे मनुष्यों में तमाम तरह की बीमारियां जैसे कैंसर इत्यादि बहुत तेजी से बढ़ा है। इसलिए हमें किसानों को जागरूक करना है कि रासायनिक कीटनाशकों को अनुशंसित मात्रा में ही उपयोग करें।

प्रवीण कुमार, वनस्पति संरक्षण अधिकारी द्वारा जिले में चूहे का प्रकोप एवं नियंत्रण और फॉलआर्मी वर्म के प्रबंधन, मित्र एवं शत्रु कीटों की पहचान के बारे में बताया गया। अभिषेक सिंह बादल, सहायक वनस्पति संरक्षण अधिकारी द्वारा जिले की प्रमुख फसलों के रोग और कीट तथा प्रबंधन, मनुष्य पर होने वाले कीटनाशकों का दुष्प्रभाव तथा कीटनाशकों का सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग, साथ ही साथ केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदित रसायन का कीटनाशकों के लेवल एवं कलर कोड पर आधारित उचित मात्रा में ही प्रयोग करने का सुझाव दिया। साथ ही भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के एनपीएसएस (नेशनल पेस्ट सर्विजिलेंस सिस्टम) एप के उपयोग एवं महत्व की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान केंद्र के अधिकारियों द्वारा आईपीएम प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। जागरूकता के लिए कृषकों को फेरोमोन ट्रेप, ल्यूर, जैविक कीट-रोग नियंत्रण हेतु उपयोगी सामग्री जैसे-बेबेरियाना, माइकोराइजा, ट्राइकोडरमा, फल छेदक कीट नियंत्रण के लिए विशेष फेरोमोन ट्रेप इत्यादि भी सेंपल के रूप में दिए गए।

एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधरोपण

प्रशिक्षण समन्वयक डॉ. एमके भार्गव, वरिष्ठ वैज्ञानिक (सस्य विज्ञान) द्वारा समन्वित कीट-रोग नियंत्रण के आयामों के साथ-साथ प्राकृतिक खेती की ओर भी जागरूकता के बारे में बतलाया गया। जेसी गुप्ता वैज्ञानिक (पौध संरक्षण) द्वारा भी प्राकृतिक खेती में फसल सुरक्षा घटकों की जानकारी दी गई। जिसमें आईपीएम के विभिन्न आयामों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन किसानों को खेत भ्रमण करा कर के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में 70 से अधिक प्रगतिशील किसानों और राज्य कृषि कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। 29 अगस्त को एक पेड़ मां के नाम अभियान में कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी पर पौधरोपण भी किया गया जिसमें आंवला, नीम एवं बकाइन के पौधे रोपित किए गए।

संचालक विस्तार सेवाएं ने बैतूल में भ्रमण के दौरान कहा

गेंदा की खेती में तकनीकी ज्ञान के साथ कृषि विज्ञान केंद्रों की अहम भूमिका

बैतूल। जागत गांव हमार

गत दिवस डॉ. डीपी शर्मा, संचालक विस्तार सेवाएं, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, बैतूल का भ्रमण किया गया। सर्वप्रथम डॉ. शर्मा ने रावे छात्राओं द्वारा तैयार की गई मशरूम उत्पादन इकाई का अवलोकन किया और बैतूल बाजार की रावे छात्राओं के संपर्क कृषक मुकुल वर्मा के प्रक्षेत्र का भ्रमण किया जिनके द्वारा लगभग 1 एकड़ प्रक्षेत्र में गेंदा की खेती की जा रही है, उन्हें गेंदा की खेती से संबंधित तकनीकी जानकारी दी और इस कार्य में कृषि विज्ञान केन्द्र की भूमिका की सराहना की। तदोपरांत केन्द्र परिसर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम अंतर्गत पौधरोपण किया और नवीन स्थापित प्राकृतिक खेती इकाई का उद्घाटन किया। इस दौरान केन्द्र प्रमुख डॉ. व्हीके वर्मा ने प्राकृतिक खेती के घटक जीवामृत एवं बीजामृत की पांच-पांच लीटर की पेकिंग कम दामों पर किसानों के लिए उपलब्ध कराने की जानकारी दी और संचालक विस्तार सेवाओं द्वारा इस संबंध में किए जा रहे अन्य कार्यों की समीक्षा की। साथ ही अजोला उत्पादन इकाई, केंचुआ उत्पादन इकाई, हाइड्रोपोनिक इकाई का भी भ्रमण किया। केन्द्र पर स्थापित संग्रहालय का अवलोकन किया और उसमें सुधार किए जाने के सुझाव दिए।

प्राकृतिक खेती इकाई में लगाई गई अरहर फसल का भी निरीक्षण किया

डॉ. डीपी शर्मा द्वारा केन्द्र के फसल संग्रहालय का भ्रमण किया और अरहर की उन्नत किस्म भीमा जो कि सीड हब परियोजना अंतर्गत लगाई गई है, का निरीक्षण किया। उसी के साथ प्राकृतिक खेती इकाई में लगाई गई अरहर फसल का भी निरीक्षण किया और वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे इस कार्य की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में धानुका द्वारा आयोजित एक दिवसीय धानुका मित्र प्रशिक्षण में कृषकों को संबोधित किया और इन धानुका मित्रों की सार्थकता पर प्रकाश डाला। इस दौरान केन्द्र के प्रमुख डॉ. संजीव वर्मा ने केन्द्र द्वारा चलाई जा रही किसान उन्नमुखी परियोजनाओं की जानकारी दी और आज के इस कार्यक्रम को विकसित भारत अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी प्रदान की। इस दौरान केन्द्र के अन्य वैज्ञानिक आरडी बारपेटे, डॉ. मेघा दुबे, डॉ. संजय जैन, डॉ. एमपी इंगेल, नेपाल बारस्कर आदि उपस्थित थे।

कृषि कॉलेजः तीसरे चरण में बड़े पैमाने पर पौधरोपण

रीवा। जागत गांव हमार

कृषि महाविद्यालय रीवा में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अन्तर्गत पौधरोपण कुलगुरू प्रो. पीके मिश्रा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के निर्देशन में अधिष्ठाता प्रो. एसके त्रिपाठी कृषि कॉलेज रीवा व कृषि विज्ञान केन्द्र रीवा के प्राध्यापक वैज्ञानिक कर्मचारी के साथ यूजी पीजी के छात्र छात्राओं के सहयोग से किया गया। यह कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से मिले दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीपल का पेड़ लगा कर किया गया है। इस अवसर पर डॉ. बीएम मौर्य, डॉ. आरपी जोशी, डॉ. वीके सिंह, डॉ. टीके सिंह, डॉ. अखिलेश कुमार, डॉ.राधा सिंह, डॉ. एके गिरी, डॉ. दिव्या सिंह डॉ. केएस बघेल, अभिषेक सोनी, अनुपमा अग्रवाल, महेंद्र कुमार मिश्रा, छत्रसाल पांडेय, हरीश द्विवेदी, टी बैगा, गुल सुप्रिया राय, भावना पार्थि, संतोष महोबिया, सरोज तिवारी, कमलेश वर्मा, जेपी तिवारी, सिद्धू और छात्र-छात्राओं की भूमिका उल्लेखनीय रही।

कृषि वैज्ञानिकों ने खरीफ फसलों में रोग, कीट सर्वेक्षण और नियंत्रण के बताए उपाय

किसानों की फसलों में देखा गया सफेद मक्खी का प्रकोप

नरसिंहपुर। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर के वैज्ञानिकों के चिकित्सीय टीम ने सोयाबीन ,अरहर ,गन्ना व मक्का फसलो मे सर्वेक्षण उपरांत पाया कि सोयाबीन की जेएस 21-72 जाति को छोड़कर के लगभग सभी जातियों में आशिक से 30: तक पीला मोजक का आपतन पाया गया। साथ ही सोयाबीन की फसल में कहीं-कहीं अल्टरनेरिया एरियल ब्लाइट व ईल्ली का प्रकोप भी मिला। पीला मोजक रोग विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसका फैलाव सफेद मक्खी द्वारा किया जाता है। यदि हम रोग फैलने वाले सफेद मक्खी को नियंत्रित कर लें, तो रोग का प्रसारण नहीं हो पाएगा। केन्द्र के पादप संरक्षण वैज्ञानिक डॉ. एसआर शर्मा द्वारा फसलों में कीट और रोगों के नियंत्रण के लिए नाशको की संस्तुति दी है, जो फसल वार निम्नवत है-सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्जाम 125 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर या ऐसीटामीप्रिइड 125 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर दस दिन के अन्तर पर या फीप्रोनील प्लस इमिडाक्लोप्रिड 200 से 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी के साथ छिड़काव करके नियंत्रण कर सकते हैं। याद रहे की 10 दिन के अंतराल पर कीटनाशकों को बदलकर कम से कम दो छिड़काव करें। एरियल ब्लाइंट रोग के नियंत्रण के लिए टेबूकोनोजोल प्लस मेंकोजेब के 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। जिस खेत के सोयाबीन में सफेद मक्खी वह ईल्ली दोनों का प्रकोप हो उसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्जाम प्लस लेमडाहेलोथ्रीन 80 से 100 मिली लीटर प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ छिड़काव करके नियंत्रण कर सकते हैं। यदि यह दवा उपलब्ध नहीं होती है, तो इमिडाक्लोप्रीड प्लस बीटा साईफ्लोथ्रिरीन 150 मिली प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। गन्ने में सर्वेक्षण के उपरांत पाया गया की सभी क्षेत्रों में सफेद मक्खी का प्रकोप बहुत ज्यादा है।

किसान पानी के साथ मिलाकर दवा का करें छिड़काव

सफेद मक्खी के प्रभाव से 5 से 10: तक गन्ने की उपज वह एक से दो प्रतिशत तक चीनी प्रतिशत कम हो सकता है। इसको पहचान के लिए किसानों को देखना होगा कि गन्ने की पत्तियां पीली पड़ती है। गन्ने के पत्तियों के पीछे सफेद काली उभरी कतार मे संरचना बनकर चिपकी रहती है जो रगड़ने पर काले रंग का दिखेगा। कभी-कभी ज्यादा प्रकोप होने पर काला पाउडर पत्तियों पर दिखाई देता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया गन्ने में बाधित होती है। इसके नियंत्रण के लिए थाईओमेथाकजाम 25:150 ग्राम प्रति एकड़ या डिफेनथुरान 250 ग्राम प्रति एकड़ 250 से 300 लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव करें। अगर यह दावा भी प्राप्त नहीं होती है तो फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्राइड 40: को 150 से 200 मिलीलीटर दवा 300 लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव करें। जैसा देखा जाता है कि गन्ने में नाइट्रोजन खाद का प्रयोग ही ज्यादातर किसान भाई करते हैं जहां नाइट्रोजन खाद का ज्यादा प्रकोप होता है या खेत में पानी लगता है वहां सफेद मक्खी का प्रकोप ज्यादा होता है। किसान भाई ध्यान रखें कि गन्ने के लिए संस्तुत नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश तीनों खाद को मिलाकर प्राय: बोवनी में प्रयोग करें। किसानों के खेतों यह भी देखा गया मक्के के खेत में फालआर्मीवर्म का प्रभाव कहीं-कहीं दिख रहा है। क्योंकि फॉलआर्मीवर्म मक्के का बहुत ही नुकसानदायक कीट है। यह पत्तियों के गोफन में घुसकर के खाता है। भुट्टे को भी नुकसान करता है जिससे कि भुट्टे का बाजार दर कम हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए ऐमामेक्टिन बेंजोएट 80 ग्राम प्रति एकड़ या प्रोफेनोफास प्लस साइपरमैथ्रीन 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। इससे फसल सुरक्षित रहेगी।

लाल मकड़ी को नियंत्रित करना अति आवश्यक

अरहर की फसल में कहीं-कहीं स्टेरीलिटी मोजेक रोग दिखाई दे रहा है। इसमें अरहर की पत्तियां छोटी पीली पड़ जाती है। शाखाएं कम निकलती है। फल-फूल के समय इसमें बहुत ही कम फूल और फल आता है। यह रोग विषाणु के द्वारा उत्पन्न किया जाता है जिसका प्रसारण माइट के द्वारा होता है। अत: माइट (लाल मकड़ी) को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। लाल मकड़ी के नियंत्रण के लिए प्रोपेजाइट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ या एबोमेक्टीन 0.75 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या बाईफेनाजेट 1 मिली प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। यदि हेकसीथीओक्स उपलब्ध हो तो 1-1.25 मिली लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। जैसा किसान भाई भी जानते हैं कि माइट का प्रकोप होने पर पत्तियां नीचे की तरफ उल्टी नाव जैसी बनाती है और इसके नियंत्रण के लिए उपरोक्त रसायनों के साथ ही कुछ कीटनाशक जैसे डाईफेनथुरान, इमिडाक्लोप्रीड या प्रोफेनोफॉस साइपमेथ्रीन का भी प्रयोग कर सकते हैं।

कृषि वैज्ञानकों की सलाह-किसान बांस के पास थाला बनाकर पौध का रोपण करें

मचान पर कद्दूवर्गीय सब्जियां और नीचे प्याज, धनियां लगाकर कमाया जा सकता है मुनाफा

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार, वैज्ञानिक डॉ. एसके सिंह, डॉ. यूएस धाकड़, डॉ. एसके जाटव, डॉ. आईडी सिंह और जयपाल छिगारहा द्वारा विगत दिवस ग्राम महाराजपुरा, ब्रजपुरा एवं सूरजपुर के किसानों के प्रक्षेत्र पर कद्दूवर्गीय सब्जियों का भ्रमण के दौरान पाया गया कि लौकी, करेला, गिल्की, खीरा, आदि की फसल में मृदुरोमिल आसिता (डाउनी मिलड्यू) एवं रस चूसक कीटों के प्रकोप से फसल प्रभावित हो रही है। मृदुरोमिल आसिता (डाउनी मिलड्यू) के नियंत्रण के लिए टेबुकोनाजोल + सल्फर का 2.5 ग्रा/ली और रस चूसक व इल्रियों के लिए बीटा-साइफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिली/लीटर पानी की दर से छिड़काव कर नियंत्रित किया जा सकता है। जिले में कुछ किसान खरीफ मौसम में प्याज की खेती कर रहे हैं। प्याज की फसल में अत्यधिक खरपतवार होने के कारण फसल प्रभावित हो रही है। इसके नियंत्रण के लिए प्याज रोपण के 30-35 दिन के पश्चात ऑक्सीफ्लोरफेन 2 मिली/लीटर एवं क्विजालोफॉप 1.5 मिली/ली पानी की दर से छिड़काव कर खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है।

खरीफ मौसम में कद्दूवर्गीय की प्रमुख सब्जियों जैसे - लौकी, करेला, खीरा, गिल्की (लताओं वाली) की अगेती किस्मों को मचान विधि से किसान खेती कर अच्छी उपज प्राप्त कर रहे हैं। मचान विधि से तात्पर्य है कि कद्दूवर्गीय सब्जियों की अगेती फसल प्राप्त करने के लिए नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। इसके बाद मुख्य खेत में जड़ो को बिना नुकसान पहुंचाए रोपण किया जाता है। यदि मुख्य खेत में कोई फसल लगी है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए की उपरोक्त फसल की कटाई कब होनी है। उसके 12-15 दिन पूर्व 15×10 सेमी. के आकार की पालीथीन बैग में पौध तैयार करते हैं। मचान विधि से लौकी, करेला, खीरा, गिल्की आदि सब्जियों की खेती सफलता पूर्वक की जा सकती है। इस विधि से खेती करने के लिए खेत में बांस या तार का जाल बनाकर सब्जियों की बेल को जमीन से ऊपर पहुंचाया जाता है। मचान विधि से खेती करने के लिए एक एकड़ क्षेत्रफल में मचान के लिए 8 फिट लम्बाई के 600 बांस, 20 किग्रा रेशा धागा, 15 किग्रा पतला तार तथा 10 किग्रा पतली रस्सी, मचान के लिए 10 × 10 फीट की दूरी पर बांस लगाएं। बांस के पास थाला बनाकर पौध का रोपण करें। बांस तीन वर्ष तक उपयोगी होता है। इस विधि से खेती करने से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लौकी, करेला, गिल्की, खीरा आदि के फल अच्छे आकार, स्वस्थ, स्वच्छ एवं शीघ्र तैयार हो जाते हैं। मचान पर कद्दूवर्गीय सब्जियां और नीचे प्याज, धनियां लगाकर मुनाफा कमाया जा सकता है। उपरोक्त विधि से खेती करने में लगभग 20,000 रुपए प्रति एकड़ व्यय होता है और लाभ 80,000 से 1,00,000 तक होता है।

फसलों में लगने वाले कीटों रोगों के नियंत्रण की दी जानकारी

रीवा। जागत गांव हमार

अधिष्ठाता डॉ. एसके त्रिपाठी कृषि कॉलेज रीवा के मार्गदर्शन एवं डॉ. एके पांडेय प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र रीव के निर्देशन में विकसित भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत पौध सरंक्षण वैज्ञानिक डॉ. अखिलेश कुमार द्वारा कृषकों के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ-साथ गांव खोखम में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता जागरुकता पर रैली निकालकर साफ सफाई का संदेश दिया गया। इस समय फसलों में लगने वाले कीटों एवं रोगों के नियंत्रण के लिए जानकारी दी।

पत्ती एवं फलों को काटने या इल्ली का प्रकोप दिखाई देने पर एमामेक्टिन बेन्जोएट 5 प्रतिशत एसजी की 200 ग्राम/हे. एवं रोग दिखाई देने पर कार्वेन्डाजिम एवं मैन्कोजेब की मिश्रित दवा की 700 ग्राम/हे को 500 लीटर पानी में डालकर छिडकाव करें। फसल खरपतवार, उड़द, सोयाबीन, अरहर एवं मूंग में 20 से 25 दिन में सकरी व चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए प्रोपेक्विजाफाप एवं इमेजाथापर की मिश्रित दवा 800 एमएल/एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर डालें।

सीधी बोवनी और रोपाई वाली चावल में पाईराइजोसल्फूरान 80 ग्राम/एकड़ की दर से रेत में मिलाकर डालें। चूसने, लपेटने एवं काटने वाले कीट का प्रकोप होने पर थायोमे थोक्जाम एवं लैम्बडासायलोथ्रीन की मिश्रित दवा की 300 मिली /हेक्टर करना चाहिए।

अनूठी पहल ने पर्यावरण को नुकसान से बचाया, पौधों को भी दिया रक्षा-कवच

-बड़वानी में वन विभाग के अफसरों ने उठाया अनूठा कदम, तब सफल हुआ प्रयोग

पौधारोपण के बाद फेंक दी जाने वाली काली पॉलिथीन को किया रीसायकल

बड़वानी। जागत गांव हमार

वर्षाकाल में पूरे देश में करोड़ों पौधे रोपे जाते हैं, किंतु उन्हें रोपते समय उनकी जड़ों को संभालने वाली काली पन्नी (मिट्टी से भरा पॉलीबैग, जिसमें पौधा बड़ा होता है) को अकसर पौधारोपण वाली जगह पर ही फेंक दिया जाता है। फिर वह पॉलीबैग या तो मिट्टी को प्रदूषित करता है या वर्षाजल के साथ बहकर किसी नदी-नाले में पहुंच जाता है। इससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है और पौधारोपण के पुण्य का क्षय भी होता है। किंतु मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के वन अधिकारियों ने इससे बचने के लिए अनूठा प्रयोग किया, जो सफल रहा है। बीते वर्ष बड़वानी जिले के सेंधवा नामक कस्बे में जहां-जहां पौधारोपण हुआ, वहां एक-एक वनरक्षक तैनात कर दिया गया। वनरक्षकों ने पौधारोपण के बाद फेंकी गई सभी काली पन्नियों को एकत्रित कर वन विभाग के कार्यालय पहुंचा दिया। अकेले सेंधवा कस्बे से दो क्विंटल पन्नियां एकत्रित हुईं, जिन्हें विभाग ने रीसाइकल करने वाली कंपनी को बेचा। इससे जो धनराशि प्राप्त हुई, उससे पौधों के लिए 200 ट्री-गार्ड खरीद लिए।

पूरे जिले में लागू होगा प्रयोग

यह सफल प्रयोग इस बार पूरे बड़वानी जिले में लागू किया जा रहा है। बड़वानी जिला घने जंगल वाली सतपुड़ा वन रेंज में बसा है। बड़वानी वन मंडलाधिकारी आइएस गाडरिया के अनुसार इस वर्ष जिले को 1250 हेक्टेयर क्षेत्र में साढ़े सात लाख पौधे रोपने का लक्ष्य मिला है। पूरे जिले में यह प्रयोग लागू करने से साढ़े सात लाख काले पालीबैग सतपुड़ा के जंगल और मिट्टी में मिलने से रोके जाएंगे। जहां-जहां पौधारोपण होगा, वहां-वहां एक वनरक्षक को तैनात कर खाली पालीबैग एकत्रित करवाए जाएंगे। इन्हें वन विभाग के रेंज कार्यालय पर एकत्रित कर रीसाइकल करने वाली कंपनी को बेचा जाएगा। इस बार जिले से 3750 क्विंटल वजन के पॉलीबैग एकत्रित होने का अनुमान है। इसकी बिक्री से मिलने वाली धनराशि में कुछ और पैसा मिलाकर वन विभाग ट्री-गार्ड खरीदेगा या पौधे रोपने के लिए गड्ढों की खोदाई करवाएगा।

यह होंगे लाभः जंगल दूषित नहीं होगा, मवेशी भी बचेंगे

बड़वानी क्षेत्र के वन रेंजर गुलाबसिंह बर्डे के अनुसार पौधारोपण और पॉलीबैग एकत्रीकरण को लेकर इस बार पूरी तैयारी है। पालीबैग जंगल या मिट्टी में न फेंकने के कई लाभ होंगे। एक लाभ यह भी होगा कि इसे वन्यजीव या मवेशी नहीं खाएंगे और असामयिक मृत्यु से बचेंगे। इसके अलावा पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा, जंगल की मिट्टी खराब नहीं होगी। पालीबैग से होकर रिसने वाला जो वर्षाजल भूजल को दूषित कर सकता था, वह भी नहीं कर सकेगा।

ऐसे आया विचार

बीते वर्ष सेंधवा कस्बे में वन मंडलाधिकारी के रूप में अनुपम शर्मा पदस्थ थे। उन्होंने एक पौधारोपण कार्यक्रम में देखा कि पौधा रोपने के बाद काले पालीबैग वहीं पर फेंके जा रहे हैं। उन्हें यह नागवार गुजरा। उन्होंने योजना बनाई कि अब सेंधवा कस्बे में जहां पौधारोपण होगा, वहां एक वनरक्षक भेजकर सारी पन्नियां एकत्रित करवाई जाएंगी। शर्मा ने पॉलीबैग रीसाइकल करने वाली कंपनी से बात की और करीब दो क्विंटल खाली पालीबैग दिए। इससे जो आय हुई, उसे वन समिति के बैंक खाते में डालकर पौधों के लिए ट्री-गार्ड खरीदने सहित सामाजिक जनजागरूकता में खर्च किया गया।

सतपुड़ा की कोख में रोपेंगे नीम

बड़वानी सतपुड़ा रेंज की गोद में बसा है, इसलिए अभियान के तहत यहां ऐसे पौधे लगाए जाएंगे, जो बड़े होकर विशाल बन जाते हैं और जंगल में अच्छी तरह फलते-फूलते हैं। इनमें नीम, करंज, पीपल, बरगद, अशोक, गुलमोहर, चिरोल, सलाई, धावड़ा, रोसा, पलाश आदि लगाए जाएंगे। आबादी के समीप सुरक्षित क्षेत्र में आम, जामुन, चीकू, जाम, नींबू, आंवला जैसे फलदार पौधे भी लगाए जाएंगे।

शहडोल में किसानों को कीटनाशक के छिड़काव से रोका

नए नियम! अब ड्रोन उड़ाना है तो बनाना होगा पासपोर्ट

शहडोल। जागत गांव हमार

खेती के लिए ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया में पासपोर्ट की अनिवार्यता ने शहडोल जिले के किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कृषि विभाग ने ड्रोन का प्रशिक्षण लेने से पहले पासपोर्ट जमा कराना अनिवार्य किया है, जिसके चलते जिले में अभी तक एक भी किसान ड्रोन नहीं खरीद पाया है। उपसंचालक कृषि आरपी झारिया ने बताया कि पासपोर्ट को एक वैध परिचय पत्र के रूप में मान्यता दी गई है, और किसानों को प्रशिक्षण से पहले इसे जमा करना आवश्यक है। इस शर्त के कारण कई किसान ड्रोन खरीदने में हिचकिचा रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य इस जिले के युवा आधुनिक खेती में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन पासपोर्ट की अनिवार्यता ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। किसान अरुण तिवारी और मनोज सिंह का कहना है कि वे कृषि में नई तकनीकें सीखने के इच्छुक हैं, लेकिन पासपोर्ट बनवाने की जद्दोजहद उन्हें रोक रही है। शहडोल में कृषि अभियांत्रिकी विभाग के उपयंत्री रितेश पयासी ने कहा कि शहडोल में अभी तक एक भी किसान ने ड्रोन के लिए आवेदन नहीं किया है, और न ही ड्रोन खरीदा है। पासपोर्ट की अनिवार्यता के कारण किसान ड्रोन का महत्व समझने में असमर्थ हैं।

सोयाबीन की फसल में उपयोग

ड्रोन का उपयोग विशेष रूप से सोयाबीन की फसल में कीटनाशकों और खाद के छिड़काव के लिए किया जाता है, जिससे उपज में सुधार होता है। कई किसान ड्रोन खरीदने के इच्छुक हैं, लेकिन पासपोर्ट की बाध्यता उन्हें रोक रही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) के दिशा-निर्देशों के अनुसार पासपोर्ट को नागरिकता पहचान के लिए सबसे विश्वसनीय दस्तावेज माना गया है।

पासपोर्ट धारी किसान है कहां

शहडोल जिले में ऐसे किसानों की संख्या बहुत कम है जिनके पास पासपोर्ट है। इसी कारण से अब तक किसी भी किसान ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। इस शर्त के चलते किसानों का रुझान भी कम हो गया है, और जिले से भोपाल में ट्रेनिंग के लिए भेजने की प्रक्रिया भी रुक गई है।

15 हजार में ड्रोन प्रशिक्षण

ड्रोन प्रशिक्षण का खर्च 15,000 रुपए है, जिसे किसान को खुद वहन करना होता है। इसके बाद ड्रोन की खरीद भी किसान को खुद करनी पड़ती है, जिसकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए तक हो सकती है। कृषि अभियांत्रिकी विभाग किसानों को ड्रोन के फायदे बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक किसानों ने इसमें कोई खास रुचि नहीं दिखाई है।

मध्य प्रदेश ने फिर से जीता सोया प्रदेश का खिताब

भोपाल। मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे अपने प्रतिद्वंद्वी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए देश में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य बनने का गौरव एक बार फिर हासिल कर लिया है।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ मप्र देश में सोयाबीन उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर आ गया है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में महाराष्ट्र 5.23 मिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पर है। देश के कुल उत्पादन में महाराष्ट्र का योगदान 40.01 प्रतिशत है, जबकि राजस्थान 1.17 मिलियन टन उत्पादन के साथ तीसरे नंबर पर है और देश के कुल सोया उत्पादन में राजस्थान का योगदान 8.96प्रतिशत है। वहीं मप्र में सोयाबीन का उत्पादन 5.47 मिलियन टन है और देश में प्रदेश के सोयाबीन उत्पादन का योगदान 41.92 प्रतिशत है।

पिछले दो साल में पिछड़ गया था मप्र

पिछले दो सालों में मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन में कमी आने से मध्य प्रदेश पिछड़ गया था। वर्ष 2022-23 में महाराष्ट्र 5.47 मिलियन टन उत्पादन के साथ प्रथम स्थान पर था और देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में 42.12प्रतिशत का योगदान था और जबकि मध्य प्रदेश 5.39 मिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पर था। देश के कुल सोया उत्पादन में योगदान 41.50 प्रतिशत था।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)